

+ अबरे छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

हल्द्वानी, सोमवार 13 अक्टूबर 2025 हल्द्वानी संस्करण: वर्ष 23 अंक 48 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

कार्तिक कृष्ण प्लॉ 7 बिहारी मार्ग 2082 20 बीजल ताली 1447 हिजरी नई दिल्ली, मुफ्कानगर, देहादुन, हल्द्वानी, मुदावाद, बोली, भेट व लखनऊ से प्रकाशित

ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था: चिंदंबरम

कहा: इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

कर्सोली (हिमाचल प्रदेश) वार्ता



पूर्व गृह एवं वित्त मंत्री पी. चिंदंबरम ने 1984 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार की आलोचना की और इसे गलत रही का बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कोरोन अपनी जान देकर चुकाई।

खुशबूति सिंह साहित्य महासभा 2025 में बोलते हुए, पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि विद्युत पूजा स्थल से सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का उपयोग किया गया। चिंदंबरम ने कहा कि जून 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना, पुलिस, खुफिया और सिविल सेवाओं का संचयी निर्धारण था।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस आलाकमान नाराज

नई दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिंदंबरम के बयान (ऑपरेशन ब्लू स्टार) पर पार्टी के अंतर्गत वित्तीय विवाद में गया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके बयान को लकर नामांगी जाहिर की है। सूतों के मुताबिक, कांग्रेस आलाकमान भी उनके बयान से नाप्रभावित रही है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक उनके हालिया बयान से नाखुश हैं। इसमें वित्तीय विवाद का आलाकमान का विवरण दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्युत पूजा सेवाओं के सब कुछ दिया है, उन्हें सावधानीपूर्वक बयान देना चाहिए। बार-बार ऐसे बयान देना सही नहीं है। इससे पार्टी की सैन्य अधिकारी का कोई अनादर नहीं है, लेकिन वह (ब्लू स्टार) स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने का गलत तरीका था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप इसके लिए केवल इंदिरा गांधी को दोषी नहीं ठहरा सकते। चिंदंबरम लेखिका हार्दिक बाबेजा के साथ वे विल शट यू मैड़म; मार्ड लाइफ़ : कॉन्फिलक्ट पर एक चर्चा के दोरान एक सभा को संबोधित था। ऐसी खबर थी कि

■ 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना, पुलिस, खुफिया और सिविल सेवाओं का संचयी निर्धारण था

हमारा दिल बड़ा है,
पाकिस्तान से पूछिए
क्या दिवकर: मुताबिकी



नई दिल्ली। अफगानिस्तान के विवेस मंत्री अमरीन खान मुताबिकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव और भारत की अफगानिस्तान से बढ़ती नजदीकों से संवादित कई सावधानों के जवाब दिया। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के द्वारा अफगानिस्तान के विवेस मंत्री अमरीन खान मुताबिकी ने साफ किया कि उनके देश को पाकिस्तान या भारत के साथ किसी तरह की परेशानी नहीं है। जब उन्हें पूछा गया कि क्या भारत की अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती की बजाए से पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया है, तो उन्होंने कहा कि ये सावधानीपूर्वक विवरण देना सही है। बीजेपी प्रवर्तन के बाहर से भारतीयों ने सभा पड़ी है। इससे पार्टी को जानकारी मिली है।

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास कमज़ोरियों से भरा नई दिल्ली।

चिंदंबरम के बयान पर

कांग्रेस का इतिहास

पाक की बेचैनी

इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सात दिवसीय भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पाक व अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इशारा करती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काफी अंदर घुसकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जाहिर है टीटीपी पर सर्जिकल स्ट्राइक तो एक बहाना लगती है असल मकसद इसके पीछे कुछ और लगता है। लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी को पचा नहीं पा रहा है। हालांकि टीटीपी और पाक के बीच संघर्ष कोई नया नहीं है। टीटीपी को हमेशा पाकिस्तान अपने लिए खतरा मानता है और वह यह आरोप भी लगाता रहता है कि उसको शह अफगानिस्तान से मिल रही है। ताजा मामले में भी यही कह रहा है कि टीटीपी के चिरुद्ध सैन्य कार्रवाई की है। इसी तरह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रकारां के सामने विस्तार से बात की है। मुत्ताकी ने पाक पर आरोप लगाया और कहा कि उसने खुद ही अपने कबालाई इलाकों में सैन्य अभियान चलाकर हजारों लोगों को बेघ किया था, जिनमें से कई शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान में रह रहे हैं। मुत्ताकी ने बताया कि ये लोग पाक से आए हैं और अफगान धरती पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं और ये लोग तब आए थे जब अमेरिका और उसकी समर्थित सरकार अफगानिस्तान में थीं, तब इन्हें जगह दी गई थी और अब ये लोग हमारी देखरेख में शांति से रह रहे हैं। मुत्ताकी का यह भी कहना था कि पाकिस्तान अफगान सीमा जिसे ड्यूरूंड लाइन के नाम से भी जाना जाता है, 2400 किमी से ज्यादा लंबी है और इसको नियंत्रित करना आसान नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि न इसे चंगें खां नियंत्रित कर सका और न ही अंग्रेज। इसको ताकत के बलबूते नहीं संभाला जा सकता। उन्होंने चेतावनधरे लफ्ज में कहा कि पाक के पास बड़ी फौज और बेहतरीन खिफिया एंजेसी हैं फिर भी वे इसे खुद क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। इस समय कतर और सऊदी अरब

के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच कोई सैन्य कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुत्ताकी ने साफ कहा कि अगर वे शांति व अच्छे रिश्ते नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के लिए और भी विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अफगानिस्तान शांति विश्वास रखता है। बड़ी बात मुत्ताकी ने कही वह यह है कि पाक अपने यहां आतंकी समूहों को क्यों काबू नहीं कर सकता है और अपने ही लोगों को खतरे में डालकर कुछ लाभ को खुश करने की क्यों कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह कहा कि कुछ ताकतें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा रहा है जहां तक बात भारत की है, अफगानिस्तान के साथ विदेश मंत्री ने उसको सराहा है यह बड़ी सफलता है।

निजी कॉलेज परिसर ने सुरक्षा सुनिश्चित करें

परिचम बंगाल के दुर्गारु में मेडिकल छात्रों के साथ हुए दुकूम की वारदात चौंकाने वाली है, हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाशत नहीं करती, वारदात में शामिल तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पुलिस अन्य की तलाश कर रही है, किसी का भी खबर नहीं जाएगा, निजी कालजों को भी दिशा दी जाएगा, और आसापास सुक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, वह लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज बताए कि वह रात के 12.30 बजे केसे बाहर आ गई, ऑडिशा में तीन सप्ताह पहले सम्पूर्ण टर पर तीन लड़कियों का साथ बलात्कार हुआ, ऑडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की और बंगाल में अगर माहिलाएं के साथ कूछ भी दोहता है तो हम इसे सामान्य मामला नहीं मानते, यह एक गंभीर मामला है।





५ स वर्ष देश भर में हुई भारी बारिशों और अधिक जल प्रबन्धन की विफलता के गंभीर परिणाम झेलने रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के बसंत कुंड क्षेत्र में तीन बड़े मॉल और आसपास की काँलोनियों में पानी की सप्लाई पूरी तरह टप हो जाने से यह सकंट फिर सूखियों में आया। इन प्रतिक्षणों का बंद करने की नीति इसलिए आ गई है क्योंकि टैकरों से इनकी जल आपूर्ति रुक गई, जल भूजल दोहन (ग्राउंड वर्टर बोरिंग) पर पहले से ही एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। यह स्थिति केवल अस्थाई तकनीकी समझा नहीं, बल्कि एक गहरे प्रशासनिक और नैतिक सकट की ओर सकेत करती है। पिछले सात दशकों में खरबारी रूपया जल प्रबन्धन पर खಚ किए जाने के बावजूद

एसा क्या है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है, जल आपूर्ति व्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। दिल्ली जल बांड के अंकड़ों के अनुसार, शहर में प्रतिदिन करीब 1,000 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जबकि उपलब्धता मुश्किल से 850 मिलियन गैलन तक पहुँच पाती है। वर्षों कुंज जैसे पांच इलाकों में भी पिछले कछुवां वर्षों से पानी की टकियों और निजों टैकरों पर निर्भार बढ़ी है। परन्तु इस बार प्रतिष्ठित पहले कहाँ आधिक भयावह हो गई क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक कारणों से टैकरों की आवाज जाही पर रोक लगा दी। इस निर्णय का सबसे बड़ा असर व्यापारिक केंद्रों जैसे मॉल्स, रेस्टरंग और दुकानों पर पड़ा है। इन मॉल्स में हजारों कर्मचारी काम करते हैं और प्रतिदिन लाखों ग्राहक आते हैं जिनमें बिना पानी के ऐसी व्यवस्था एक दिन भी नहीं सकती। शौचालय, सफाई, भोजनलालय, अग्निशमन प्रणाली, सब कुछ जल आपूर्ति पर निर्भर हैं। जब टैकरों की आपूर्ति रुकी, तो कवले व्यापार ही नहीं, आसपास के आवासीय समाज भी सकट में पड़ गए। दिल्ली सरकार ने कुछ वर्ष पहले भूजल दोहन पर सख्त प्रतिबंध लाया था जिसका उद्देश्य यह था कि गिरे जलस्तर को रोका जाए। यह पहल पर्यावरणरोग दृष्टि से आवश्यक था और लंबागत दोहन को दूल्ही के अधिक, इंश क्षेत्रों में भूजल को 300 फीट से भी अधिक नीचे पहुँचा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त रूप से विकसित की गई? जब सरकार ने ग्राउंड वॉर्ट बारिंग का

जल संकट की दस्तक दिल्ली से दूर नहीं



विनीत नारायण

तभी संभव है जब लोग खुद बदलाव का हिस्सा बनें। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और ग्रे-वॉटर रीसाइकिंग जैसे उपाय व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण स्तर पर अपनाएं जा सकते हैं। मॉल्स और हाउसिंग सासाइटीज में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्सों पर निर्भरता बढ़े दिल्ली का चर्चापान संकेत केवल एक चेतावनी है आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और बढ़ जाएं हैं। विशेषज्ञों के उठाए गए तथा 2030 तक देश के आधे बड़े शहरों 'जल-विहीन' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं इसलिए अब समय है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर दीर्घकालिक रणनीति अपनाएं और तरलबाह है कि अकबार की राजधानी फतेहपुर सीकरी रानी के अधार के कारण मात्र 15 सालों में ही उत्तराधीश गई थी। महानगरों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को सख्ती से लागू करना। जल पुनर्वापन संयंत्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाना। टैक्स के संचयन को पारदर्शन और जीपीएस-नियंत्रित बनाना। ताकि रिशतखोरी पर रोक लगे। युमना जैसी नदियों की सफाई और पुरुजीवन को प्राथमिकता देना। पानी की बवादी रोकने के लिए सख्त कानून और जनजागरूकता अभियान चलाना। इन कदमों को साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जल प्रवर्धन केवल संकट का नहीं पर चर्चा का विषय है। न बनें, बल्कि शहरी नियंत्रण की मूल नीति नहीं हिस्सा हो। दिल्ली पर आई जल संकट की दस्तक यह याद दिलाता है कि पानी के बावजूद जल नहीं। जब-जब हम इसे समझने में चक्र करते हैं, तो सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग जाता है। क्यों इसकार और जल सामाजिक अवधारणा भी इस संकट को गंभीरता से नहीं लेते, तो 'जल युद्ध' भविष्य का नहीं, चर्चापान का शब्द बन जाएगा। जलसंकट का समाधान केवल योजनाओं से नहीं, इमानदार नीति और सापूर्छिक प्रयासों से ही संभव है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

पेंशन का अधिकार शिक्षकों की मांग

भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल में शिक्षक ही हैं, जो नई पीढ़ी को ज्ञान की ज्योति प्रदान करते हैं, लिकन हाल के वर्षों में सरकारी नियतियों और न्यायिक फैसलों ने शिक्षकों के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक अंग पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग सरकारी

जो मुख्य रूप से सरकारी या सहायता प्राप्त स्कॉलों में कार्यरत है, इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ अन्य विधागां की ओर भी यदि देखा जाए तो वहां पर भी सेवारत कर्मचारियों / अधिकारी वर्ग को इस प्रकार के रीफ्रेश कोर्स करने की आवश्यकता होनी चाहिए मगर ऐसा नहीं है? क्योंकि कार्य क्षमता कसौटी अध्यापकों के लिए ही उपलब्ध हो? पचपन वर्षों की अवस्था पूर्ण कर रहे सभी प्रशासनिक, विधि, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए कोई आकलन प्रक्रिया हो जाए तो इन क्षेत्रों में भी जननानस को अपेक्षकृत बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

सरकार की नई पैंसन योजना के सबध में अध्यापकों का तर्क है कि NPS में निवेश जो खालीपाई है और मुद्रावितीक के साथ पेंशन की राशि अपवृण्यां हो साबित हो रही है। फरवरी 2017 के एक फैसले में कोर्ट ने संवानिवृति से टीक पहले वेतन बढ़ादि (नोटिशेन इंक्रीमेंट) को पेंशन में शामिल करने का निर्देश दिया, जिससे हजारों पूर्व कर्मचारियों को राहत मिली। अध्यापकों की मांग अब OPS की पूर्ण बहाली पर कोटित हो सुप्रीम कोर्ट को हालिया आदेश OPS की नैतिक और कानूनी वैधता को रेखांकित करते हैं। शिक्षक संघों द्वारा मांग की जा रही है कि पुराणी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। युनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 के तहत सरकार ने कृत गढ़त

दी है, लेकिन अध्यापक इसे अपराध मानते हैं। पेंशन को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है, क्योंकि यह सेवानिवृत्त व्यक्तियों को विनीय संरक्षा प्रदान करता है।

व्याकरण का वितान सुरक्षा प्रदान करता है।

त्रिविधीयता

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और अध्यापकों की चिंताएं, शिक्षा का अधिकार अधिकार नियम 2009 के तहत 2011 से TET को शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले में इसका और सख्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 8 तक के गैर-मानीर्ती स्कूलों में कार्यरत सभी अध्यापकों, वाहे वे RTE से पहली नियुक्त हुए हों, को TET पास करना होगा। प्रमाण इन विवरों से इसी भी TET अनिवार्य है।

अध्यापकों के पास 5 वर्ष से कम सेवा शेष है उन्हें छूट दी गई है, वे सेवा जारी रख सकते हैं लेकिन प्रमाणशान नहीं पा सकते। शेष को 2 वर्ष का समय दिया गया है, अन्यथा सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है। नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता पूर्ण मानते हुए ही कोइस सरकारी विभाग व्यक्ति का नियुक्त करता है, इन अध्यापकों ने भी ऐसा ही किया है। अब नियुक्ति के बाद निर्गत आदेशों को सेवारत शिक्षक पर लगाया जाना और वित्तीयपूर्ण प्रभाव लगाया जाना अनिवार्य है।

શહેર અલ્પ

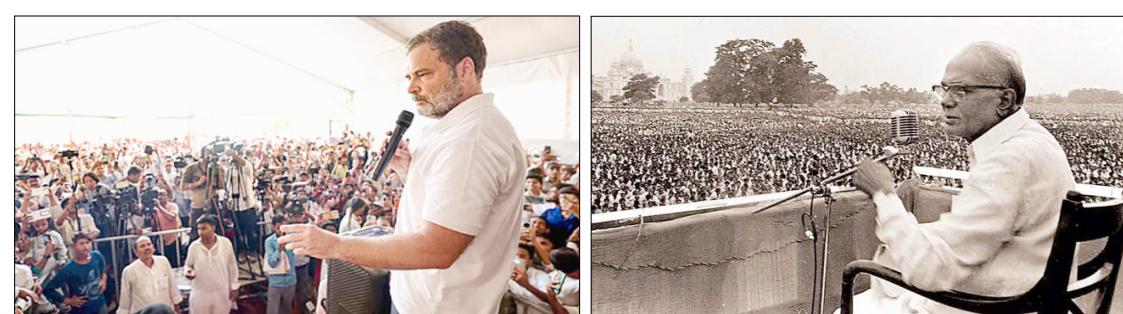
महाराष्ट्र राज्य मामले में आया, जिसमें कोर्ट ने त्याग की धारा 23 का हवाला देते हुए कहा कि ज्ञानशिक्षण योग्यता का न्यूनतम मानक है इस आदेशका का प्रभाव स्कूलों में 20-30 लाख अध्यापकों पर पड़ेगा। तमिलनाडु में ही 3 लाख से अधिक अध्यापक प्रभावित हैं, जहाँ ज्ञप्त पास रेट मात्रा 10-20 है। शिक्षकों की मांग है कि त्यां लागू होने से पहले नियुक्त अध्यापकों को ज्ञप्त दर जाए, क्योंकि उनकी अनुभव और प्रशिक्षण का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा विभाग समय-समय पर विषय आधारित एवं अन्य कौशलों पर आधारित प्रशिक्षण कराता है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महादेव ने 16 सिंबंबर 2025 को इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर करने का निर्देश दिया, स्वागत योग्य पाजिटिव पहल है जिससे आशा की किरण जगी है अध्यापक मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना का बहाल एवं लागू किया जाए एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि जौलाई 2011 को लागू हुआ इससे पहले नियुक्त किसी भी शिक्षक पर टैट नहीं थोका जाए।

(य लखक क निजा विचार ह)

राहुल को जेपी का स्मरण कराया भी जा सकता है

बि हार में परिवर्तन की जो आंधी इस समय चल रही है उसमें उस संपूर्ण क्रांति की झलक तलाश की जा सकती है जो 1947 में सोनोवालयक जयश्रुतकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप 1977 में आजादी के बाद पहली बार केंद्र में एक गैर-कांगड़ी सरकार की स्थापना हुई थी।

एक बड़ा फर्क तब और अब में वह है कि उस समय जो राजनीतिक सत्ता यानी सत्तारूढ़ कांग्रेस खलनायक के रूप में मौजूद थी वह इस समय राहुल की अगुवाई में नायकत्व की भूमिका में है। जिन साप्रदायिक तत्वों यानी तब जनसंघ और आरएसएस ने अपने राजनीतिक हतों के लिए जेपी के 1974 के छात्र-आंदोलन के पर कब्जा कर लिया था वे इस समय खलनायकों के गोले में हैं। राहुल की उम्र उस समय चार-पांच साल की रही होगी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी तब सत्ता की राजनीति से कोसों दूर थे दिल्ली में सत्ता के सारे सूत्र संजय गांधी और उनकी अतिविश्वसन कटोरी के हाथों में थे। जेपी के साथ 1972 में हुए चंबल घाटी के ऐतिहासिक दस्युआ आम-समस्य के समय से जुड़ी हाने के कारण विहार आंदोलन के दौरान भी लोकनायक का साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हआ था। विहार चुनावों को लेकर यूट्यूब चैनलों पर हाने वालों बहसों का माध्यम से और राहुल गांधी की टीम से नजदीक से जुड़े एक सांसद के जरिए राहुल तक एक संदेश पहुंचाने की कांशिश में पिछले दिनों की थी। राहुल गांधी तक संदेश यह पहुंचाना था कि उन्होंने युवा शक्ति के माध्यम से



राहुल गांधी पटना सहित बिहार के अन्य स्थानों की यात्रा एं लगातार कर रहे हैं। उनकी ऐतिहासिक वोटर अधिकार यात्रा का समापन भी पटना में ही हुआ था। विषयकी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक भी पटना में ही हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बैठक के आयोजक थे। केजरीवाल भी उस बैठक में उपस्थित थे। बाद में इंडिया ब्लॉक को धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। मेरा सुझाव यह था कि राहुल अपनी किसी पटना यात्रा के दौरान अगर जेपी के कदम कुआं स्थित निवास स्थान पहुंचकर संपूर्ण क्रांति के नायक को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर देंगे तो उसका संदेश बिहार के गांव-गांव तक पहुंच जाएगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

